बिज़नेस स्टैंडर्ड
वर्ष 12 अंक 90

तमाम आर्थिक चुनौतियां

राजधानी नई दिल्ली के जानकार लोगों के बीच एक चर्चा यह रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दूसरा कार्यकाल पहले से अलग होगा। पिछले पांच वर्ष उन्होंने अपनी और भारतीय जनता पार्टी की स्थिति मजबूत करने में खपाए। कहा जा रहा है कि अब वह अर्थव्यवस्था पर ध्यान केंद्रित करेंगे। यह भी कहा जा रहा है कि अब वह ऐसे कदम उठाने को तैयार हैं जो वह पांच साल पहले करने को तैयार नहीं थे। निश्चित तौर पर अर्थव्यवस्था को नए सिरे से गति चाहिए। तिमाही आर्थिक वृद्धि गिरकर 6 फीसदी से नीचे आ चुकी है और पांच साल के निचले स्तर पर है। पूरे वर्ष की वृद्धि का हाल भी वही है जहां से मोदी सरकार ने शुरुआत की थी। पाठकों को याद होगा कि शुरुआत में दो अंकों में वृद्धि हासिल करने की बात कही गई थी। हकीकत उससे कोसों दूर है। भारत सबसे तेज बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्था का तमगा गंवा चुका है और चीन उससे आगे हो गया है।

मैंने दो सप्ताह पहले भी इस स्तंभ में लिखा था कि यह बहुमुखी चुनौती है। कृषि, विनिर्माण और निर्यात के क्षेत्र में तमाम चुनौतियां सामने हैं। राजकोषीय और मौद्रिक नीति अलग समस्या है। दोनों ही जगह गुंजाइश बहुत सीमित है। व्यापक दलील यह हो सकती है कि पहले दौर के आर्थिक सुधारों ने जो गति प्रदान की थी, वह 15 वर्ष की निष्क्रियता के कारण गंवा दी गई। अब एक नई लहर की आवश्यकता है। क्या सरकार ऐसा कर पाएगी?

बदलाव की शुरुआत मोदी से ही करनी होगी। अब तक उन्होंने वृहद आर्थिक मुद्दों में कोई खास रुचि नहीं दिखाई है। उन्होंने परियोजनाओं और कार्यक्रमों के प्रभावी क्रियान्वयन में अधिक रुचि ली है। चुनाव नतीजे बताते हैं कि वह इसमें सफल रहे हैं। अब यह अनदेखी जारी नहीं रह सकती। प्रधानमंत्री को अपने समक्ष मौजूद प्रमुख नीतिगत कारकों की समझ पैदा करनी होगी। इसमें रुपये के बाह्य मूल्य को लेकर सरकार का रुख और देश के निर्यात को अधिक प्रतिस्पर्धी बनाने में इसकी उपयोगिता भी शामिल है। शुरुआत करें तो रुपये की मजबूती की मान्यता को त्यागना होगा।

बैंक और कंपनियां अब तक जिस तरह का वित्तीय कुप्रबंधन कर रहे हैं, उसे देखते हुए कहा जा सकता है कि बेहतर वृद्धि हासिल करना बहुत मुश्किल है। यह ऐसा दौर है जब ढेर सारे कारोबारी नए निवेश पर विचार करने के लिए पुराने कर्ज को कम करने में व्यस्त हैं और उपभोक्ता ईएमआई पर केंद्रित हैं। सरकारें मौजूदा बचत का काफी हिस्सा खपा रही हैं और बाजार की ब्याज दरों को गिरने से रोक रही हैं। इसका असर नकदी की आवक और भविष्य के निवेश पर हो रहा है। बीते वर्ष कर राजस्व लक्ष्य से पीछे रह गया, उसे गति देने की आवश्यकता है। मंदी के दौर में यह कैसे होगा?

संक्षेप में कहें तो बतौर नई वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और विदेश व्यापार और उद्योग मामलों के प्रभारी पीयूष गोयल के समक्ष काफी कुछ करने को है। दोनों को जल्द से जल्द अपना एजेंडा लागू करना होगा। इसके साथ ही मध्यम अवधि के नीतिगत लक्ष्य तय करने होंगे ताकि पूंजी का किफायती इस्तेमाल हो सके, श्रम बाजार को अधिक लचीला बनाया जा सके और बुनियादी ढांचा ऐसा हो जो उद्योग और व्यापार को प्रभावी सहयोग दे सके। इसके लिए व्यवस्थित सोच अपनाने की जरूरत है।

सुर्खियों में आने के लिए तात्कालिक कदम उठाने की प्रवृत्ति पर अंकुश लगाना होगा। वित्त मंत्री वस्तु एवं सेवा कर दरों को तार्किक बनाने और उनकी तादाद कम करने से शुरुआत कर सकती हैं। भारतीय रिजर्व बैंक को नीतिगत दरों में कटौती कर सहयोग करना चाहिए। विनिवेश को गति देने की जरूरत है, इसकी शुरुआत एयर इंडिया से हो सकती है। परंतु अगर इस दिशा में गंभीरता से आगे बढ़ना है तो यह सवाल लाजिमी तौर पर उठेगा कि खरीदार कहां हैं? क्या इसमें तथा अन्य क्षेत्रों में विदेशी खरीदारों का दायरा व्यापक किया जाना चाहिए?

इन सब बातों के अलावा कृषि, जल संबंधी अर्थव्यवस्था तथा शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने जैसे मसलों का क्या जो हमारे समक्ष मुंह बाये खड़े हैं? ये तीनों मंत्रालय नए मंत्रियों के हाथ में हैं। ऐसे में यह सवाल बना रहेगा कि आखिर उनका प्रदर्शन कैसा रहेगा? जैसा कि एक सज्जन कहते रहे हैं, देश यह जानना चाहता है।

साप्ताहिक मंथन

टी. एन. नाइनन

बिनय सिन्हा

देश की नौसैन्य क्षमता के आकलन का वक्त

हिंद महासागर एवं एशिया-प्रशांत क्षेत्र में अपने व्यापक हितों को देखते हुए भारत को अपनी नौसैनिक क्षमता की नए सिरे से समीक्षा करने की जरूरत है। बता रहे हैं **प्रेमवीर दास**

चीन के छिंग ताओ बंदरगाह पर चीनी नौसेना की मेजबानी में आयोजित इंटरनैशनल फ्लीट रिव्यू को लेकर पिछले दिनों काफी कुछ लिखा जा चुका है। इसमें भारतीय नौसेना के दो जहाजों ने भी शिरकत की। इसी तरह अगले कुछ दिनों में भारतीय एवं फ्रांसीसी नौसेनाएं भारत के पश्चिमी तट पर संयुक्त अभ्यास 'वरुणा' में हिस्सा लेंगी। बहुत लोगों का मानना है कि ऐसे संपर्क महज दिखावा होते हैं जबकि कुछ लोगों की नजर में ऐसे अभ्यासों की अहमियत कहीं ज्यादा होती है। सच्चाई इन दोनों नजरियों के कहीं बीच में है।

असल में, इन आयोजनों के दौरान समारोह और परेड जैसे कार्यक्रम होते हैं लेकिन इन सबके केंद्र में यह होता है कि शिरकत कर रहे मेहमान नौसैनिक अधिकारी मेजबान के साथ अच्छे ताल्लुक बनाएं। इस तरह इन सैन्य अभ्यासों के साथ कूटनीति का भी पहलू जुड़ा होता है। इंटरनैशनल फ्लीट रिव्यू का एक संदेश और उद्देश्य होता है। फ्लीट रिव्यू के जरिये मेजबान नौसेना की ताकत का प्रदर्शन करना तो सरलीकरण है। दुनिया इसके बारे में पहले से ही जानती है और ताकत का प्रदर्शन करने की जरूरत नहीं होती है।

फिर संयुक्त अभ्यास का सवाल आता है। ऐसा ही एक संयुक्त अभ्यास अगले महीने होने वाला है। भारत और फ्रांस दोनों ही हिंद महासागर क्षेत्र की बड़ी नौसैनिक ताकत हैं और इस क्षेत्र में उनके हित एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं। अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, जापान और सिंगापुर के साथ भारत के संयुक्त सैन्य अभ्यासों की ही कड़ी में यह अभ्यास प्रस्तावित है। हरेक अभ्यास का प्रयोजन भागीदार देशों की परिचालन जरूरतों पर निर्भर करता है। 'पासेक्स' कहे जाने वाले समुद्री अभ्यासों में ये सेनाएं नियमित तौर पर शिरकत करती हैं। इन अभ्यासों से समुद्री सेनाओं के बीच पेशेवर संपर्क बनता है और हमें अपनी गतिविधियों की समीक्षा का भी मौका मिलता है लेकिन उससे भी अहम यह है कि इससे दूसरे देशों को यह संदेश दिया जाता है कि आपसी सामरिक समुद्री हितों से द्विपक्षीय संपर्क बढ़ता है। पासेक्स किस्म कम सारगर्भित होता है लेकिन फिर भी उनकी अहमियत होती है। ये सभी बुनियादी तौर पर एक कूटनीतिक सहक्रिया की उपज होते हैं।

इंटरनैशनल फ्लीट रिव्यू और संयुक्त अभ्यासों को इसी संदर्भ में देखा जाना चाहिए। वे नौसैनिक पोतों का सम्मिलन या समारोहपूर्ण आयोजन भर नहीं होते हैं बल्कि यह प्रदर्शन होता है कि भागीदार देश मेजबान देश के साथ किस तरह संपर्क करना चाहते हैं? विदेश नीति और उससे उपजी कूटनीति देशों को प्रेरित करती है और इन अभ्यासों में शामिल होकर ये देश अपने समुद्री हितों को सुरक्षित एवं संरक्षित करने की कोशिश करते हैं। इस लक्ष्य को पूरा करने में केवल नौसेनाएं ही सक्षम होती हैं और इसीलिए विदेश नीति के लक्ष्यों के हिसाब से ऐसे आयोजन अंतरराष्ट्रीय संबंधों के मुताबिक तय किए जाते हैं।

यह तथ्य हमें भारत के अपने समुद्री हितों और दूसरे देशों के साथ संपर्क के तरीकों तक पहुंचाता है। भले ही भारत हिंद महासागरीय क्षेत्र की एक बड़ी क्षेत्रीय शक्ति है लेकिन इसके हित हिंद-प्रशांत रंगमंच तक फैले हुए हैं। इसकी वजह यह है कि भारत का आधे से भी अधिक व्यापार इस समुद्री मार्ग से ही होता है। इसके निर्विघ्न संचालन के लिए ही भारत ने दक्षिण और पूर्वी चीन सागर में अपने जहाज नियमित रूप से तैनात कर रखे हैं जो विभिन्न तटवर्ती नौसेनाओं के संपर्क में रहते हैं और छिंग ताओ में संपन्न फ्लीट रिव्यू जैसी गतिविधियों में हिस्सा लेते रहते हैं। हालांकि इस इलाके में भारतीय जहाजों की तैनाती हिंद महासागर जितनी व्यापक नहीं हैं क्योंकि हिंद महासागर में हमारे हित कहीं अधिक निहित हैं। उत्तरी हिंद महासागर में होने वाली घटनाएं हमारी बुनियादी चिंता का मुद्दा होती हैं और सेशल्स, मॉरीशस एवं मोजाम्बिक जैसे दक्षिणी तटीय देश और रियूनियन आइलैंड्स (फ्रांस) एवं दक्षिण अफ्रीका जैसे दक्षिणी देश भी हमें बढ़त दिलाने के लिहाज से अहमियत रखते हैं। यही कारण है कि इस समुद्री क्षेत्र में अपनी नौसेना के लिए परिचालन सुविधाएं मुहैया कराने के बारे में चर्चा सुनाई देती है। उत्तरी समुद्री क्षेत्र दक्षिण-पूर्व एशियाई समुद्र से लेकर स्वेज नहर तक फैला हुआ है। हमारे नौसैनिक संपर्कों को इसी संदर्भ में देखा जाना चाहिए। देखने में यह संपर्क नौसेनाओं का होता है लेकिन उसके पीछे व्यापक राष्ट्रीय हित निहित होते हैं।

क्या भारत के पास ऐसे उपाय हैं कि वह मौजूदा भू-राजनीतिक परिदृश्य के चलते पैदा होने चुनौतियों का सामना कर पाएगा? यह एक ऐसा सवाल है जिसे पूछा जाना चाहिए। इसके साथ ही यह भी देखना होगा कि क्या हम हद से ज्यादा ऊंचा दांव लगा रहे हैं? इस सवाल का जवाब हां और ना दोनों है। आज भी हम इस क्षेत्र की बड़ी नौसैनिक ताकत हैं और जरूरत पड़ने पर कभी भी अपने जहाज तैनात करने में हमें सक्षम होना चाहिए। हम अपने द्वीपीय इलाकों के जरिये अपनी पहुंच को और बढ़ा सकते हैं। दक्षिण भारत में स्थित अपने एयरफील्ड से बड़े विमानों के उड़ान भरने की क्षमता का इस्तेमाल करने से हमें केवल अपने विमानवाहक युद्धपोतों पर ही नहीं निर्भर रहना होगा। निस्संदेह हमारी कमजोरियां भी हैं। मसलन, पनडुब्बियों और लंबी दूरी तक सैनिकों और साजोसामान को लेकर जा सकने वाले जहाजों की कमी है। दुर्भाग्य से, सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के प्रतिशत आवंटन के तौर पर रक्षा आवंटन पिछले कुछ वर्षों में सबसे कम रहा है जिसकी वजह से हमारी नौसैनिक क्षमता को सशक्त बनाने में रुकावट आई है। प्रतिस्पर्द्धी मांगों के चलते यह उम्मीद करना अवास्तविक लगता है कि इस स्थिति में जल्द ही सुधार आ जाएगा लेकिन यह संभव है कि थल, वायु एवं नौसेना की ताकत की तुलनात्मक हिस्सेदारी की आलोचनात्मक समीक्षा की जाए और उन्हें नए सिरे से समायोजित किया जाए। हमारा मौजूदा रुख गत छह दशकों में बनी धारणाओं को थोड़े-बहुत बदलावों के साथ जारी रखने से अधिक कुछ नहीं है। हमें अपने राष्ट्रीय सुरक्षा हितों और उसके हिसाब से अपनी सैन्य शक्ति के बारे में एक समग्र एवं 'डे नोवो' (नए सिरे से) आकलन की जरूरत है।

(लेखक राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड के सदस्य रहे हैं। वह नौसेना की पूर्वी कमान के प्रमुख रह चुके हैं)

सिक्किम में चामलिंग के रिकॉर्ड को पछाड़ने की चुनौती

सियासी हलचल

आदिति फडणीस

दिल्ली में आए भूचाल का असर सुदूर सिक्किम में भी महसूस किया गया। देश में सबसे लंबी अवधि तक और सबसे सफल मुख्यमंत्री रहे पवन कुमार चामलिंग और उनकी पार्टी सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट (एसडीएफ) सत्ता से बाहर कर दिए गए। चामलिंग सन 1994 में पहली बार मुख्यमंत्री बने और उसके बाद पद पर बने रहे। उन्होंने मजबूती से काम किया और कई ऐसी योजनाएं पेश कीं जिनका कोई विरोध तक नहीं हुआ। सन 2013 में सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा (एसकेएम) के रूप में पहली बार विपक्ष सामने आया जिसके नेता थे प्रेम सिंह तमांग। उन्हें पीएस गोले के नाम से भी जाना जाता है।

गोले का अतीत उतार-चढ़ाव वाला रहा है। वह एसडीएफ के संस्थापक सदस्य थे। एक बार के सिवाय वह चामलिंग की हर सरकार में शामिल रहे। बाद में एसडीएफ में भ्रष्टाचार और भाई-भतीजावाद का आरोप लगाते हुए उन्होंने अलग पार्टी बना ली। सन 2009 में चामलिंग को सिक्किम में सभी 32 विधानसभा सीटों पर जीत मिली लेकिन 2014 में उन्हें 10 सीट एसकेएम के हाथ गंवानी पड़ी और उनकी पार्टी के पास 22 सीट रह गईं। शायद उन्हें अंदाजा हो गया था कि हालात बिगड़ने वाले हैं। क्योंकि गोले के पार्टी बनाने के तुरंत बाद राज्य सरकार के सतर्कता विभाग ने संभवत: चामलिंग के निर्देश पर सरकारी धन के दुरुपयोग के मामले की जांच शुरू की। यह मामला 9.5 लाख रुपये के फंड का था जो राज्य सरकार की एक योजना के तहत लाभार्थियों को गाय देने के लिए आवंटित थे। यह जांच वर्ष 2010 की है। आरोपपत्र के बाद मामला अदालत में गया और उन्हें जुर्माने और जेल की सजा का सामना करना पड़ा। भ्रष्टाचार के मामले में दोषी सिद्ध होने के बाद भी उनको दोबारा चुनाव लड़ने दिया गया जो अपने आप में रहस्यमय है। इतना ही नहीं 2018 में जब वह जेल से बाहर आए तो उनका किसी नायक की तरह स्वागत किया गया। ऐसा स्वागत आमतौर पर राजनीतिक बंदियों का होता है। सिक्किम विधानसभा में उनकी पार्टी को महज दो सीट का बहुमत है।

सिक्किम का इतिहास जटिल है और कई बार यह कहना मुश्किल होता है कि भारत में उसके विलय के नायक या खलनायक कौन थे। जैसा कि सिक्किम के पहले दीवान जॉन लाल (आईसीएस) ने कहा, सिक्किम की संप्रभुता का मान रखने और चीन की भावनाओं को समझने के बजाय भारत ने दार्जिलिंग और कलिमपोंग से नेपाली बोलने वाले लोगों की भीड़ जुटाई। स्थानीय शासक से कहा गया कि जनता ने उसके खिलाफ विद्रोह कर दिया है और इसके बाद सिक्किम को भारत में मिला लिया गया।

चामलिंग कहते हैं (शायद इसलिए क्योंकि वह नेपाली बोलने वाले हैं) कि सिक्किम के मूल लेप्चा लोगों पर तिब्बत की भूटिया जनजाति तीन सदियों तक कायम रही। उसने सामंती व्यवस्था थोपी और लिंबू और तमांग जैसी अन्य जनजातियों को समान अधिकार नहीं दिए। चामलिंग के मुताबिक स्थानीय शासक के विरुद्ध विद्रोह दरअसल एक क्रांति थी जिसने दमनकारी काजी शासन को उखाड़ फेंका। एक बार मुख्यमंत्री बनने के बाद चामलिंग को लगा कि उनको अपना जनाधार बनाना होगा। उन्होंने राज्य की नेपाली बोलने वाली आबादी में लिंबू और तमांग जैसी जातियों के लिए आरक्षण बढ़ाने की लड़ाई लड़ी। सिक्किम में 20 फीसदी आबादी भूटिया-लेप्चा है जबकि 40 फीसदी में अन्य पिछड़ा वर्ग। लिंबू, राय और तमांग कुल आबादी का करीब 20 फीसदी हैं। जब उनको आरक्षण के दायरे में शामिल किया गया तो वे स्वाभाविक तौर पर चामलिंग के मतदाता बन गए। पीएस गोले तमांग हैं। उन्होंने भ्रष्टाचार और भाई-भतीजावाद तथा प्रशासनिक नाकामी के मुद्दे पर चामलिंग को चुनौती दी। ऐसे में वही जाति चामलिंग के खिलाफ हो गई जिसे वह सशक्त बना रहे थे।

गोले के प्रचार अभियान को समर्थन मिला। सिक्किम के आइकन और प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी बाईचुंग भूटिया ने भी ऐन चुनाव पूर्व हमरो सिक्किम नामक राजनीतिक दल बना लिया। भ्रष्टाचार, नशे की लत, मानसिक बीमारियों जैसा सिक्किम का काला पक्ष दुनिया के सामने आने लगा। राज्य में छह लाख से कुछ ज्यादा लोग हैं लेकिन बेरोजगारी बहुत है। प्रति एक लाख पर 37.5 लोगों के साथ यहां आत्महत्या दर सबसे अधिक है। यह देश के औसत के तकरीबन तीन गुना है। सिक्किम के 10 में से 7 किशोर दवाओं के नशे का सेवन करते हैं। हमरो सिक्किम ने चुनाव में एक भी सीट नहीं जीती लेकिन उसके द्वारा उठाई गई समस्याएं चर्चा में आ गईं। अब यह पीएस गोले का सिरदर्द है।

गोले (जिनका चुनावी घोषणापत्र बताता है कि उन्होंने तीन बार शादी की लेकिन किसी तलाक का जिक्र नहीं) को विकास और वृद्धि के चामलिंग के रिकॉर्ड को पछाड़ना होगा। योजना आयोग के आंकड़े बताते हैं कि सिक्किम में गरीबी अनुपात देश में सबसे तेजी से घटा। यह 2004-05 के 30.9 फीसदी से गिरकर 2011-12 में 8.2 फीसदी हो गया। इस चमत्कार को समझने के लिए आपको 2014 की सिक्किम मानव विकास रिपोर्ट पढ़नी होगी जिसे यूएनडीपी ने तैयार किया। यह रिपोर्ट कहती है कि 2001 से 2012 के बीच सिक्किम का एनएसडीपी औसत 17 फीसदी सालाना की दर से बढ़ा। यह देश के सभी राज्यों में उच्चतम है। इस बीच देश का औसत 10 फीसदी रहा। सिक्किम ने 13 जलविद्युत परियोजनाओं को नकार दिया क्योंकि उनसे प्रदेश के पर्यावास को नुकसान पहुंच सकता था। उसका वैकल्पिक विकास मॉडल प्रकृति के करीब जाने का है। राज्य में रासायनिक उर्वरक का इस्तेमाल नहीं किया जाता। वहां के ऑर्किड विश्व प्रसिद्ध हैं। परिणाम? दिसंबर 2018 में सिक्किम में पहली बार एक रॉयल बंगाल टाइगर देखा गया। 10,000 फीट से अधिक की ऊंचाई पर इसका मिलना नितांत अस्वाभाविक था। प्रेम सिंह तमांग गोले को भी बिना प्रकृति से समझौता किए वृद्धि हासिल करनी होगी।

कानाफूसी

इधर कुआं, उधर खाई

मध्य प्रदेश में कांग्रेस के नेतृत्व वाली प्रदेश सरकार वर्ष 2019-20 का बजट बनाने में लगी हुई है। बजट निर्माण की प्रक्रिया उतनी सहज नहीं है जितनी कि वह नजर आ रही थी। कारण एकदम स्पष्ट है। जानकारी मिल रही है कि राज्य सरकार ने गत वर्ष हुए विधानसभा चुनाव के पहले किसानों की कर्ज माफी करने की घोषणा तो कर दी लेकिन उसके पास इसके लिए जरूरी धनराशि नहीं है। कुछ अनुमानों के मुताबिक राज्य सरकार को किसान कर्ज माफी के लिए तकरीबन 50,000 करोड़ रुपये की धनराशि की आवश्यकता है जबकि उसका खुद का खजाना खाली नजर आ रहा है। उधर विपक्ष लगातार कर्ज माफी के सवाल पर सरकार को घेरता आ रहा है। प्रदेश की सरकार बहुत मामूली बहुमत से शासन कर रही है। ऐसे में एक गलती भी उसे बहुत भारी पड़ सकती है। मामले के एक जानकार ने चुटकी लेते हुए कहा कि मुख्यमंत्री कमलनाथ की स्थिति ऐसी हो गई है कि उनके एक ओर कुंआ तो दूसरी ओर खाई है। वह आखिर जाएं तो जाएं कहां?

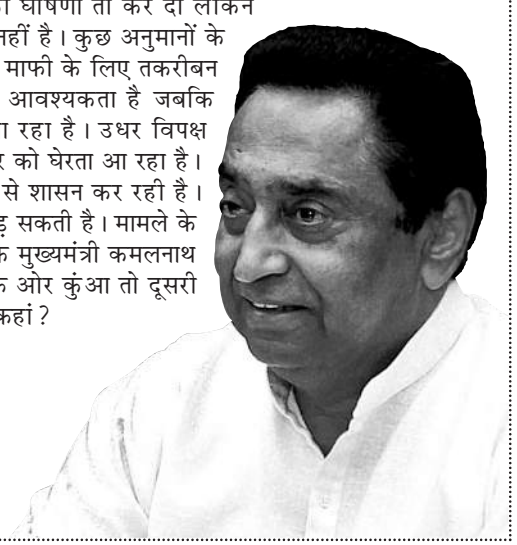

आपका पक्ष

भारत में हीट एक्शन प्लान का प्रयोग

विश्व में ग्लोबल वॉर्मिंग के बढ़ते असर को देखते हुए भारत सरकार ने एक अनूठी पहल की है। गर्मियों के समय में एयर कंडीशनर (एसी) से निकलने वाली गर्म हवा के कारण तापमान में वृद्धि होती है। वर्ष 2100 तक एसी के उपयोग से 0.5 डिग्री तापमान की वृद्धि होगी। एक स्वास्थ संगठन की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2050 तक गर्म हवा की चपेट से सालाना 2,55,000 लोगों की मौत हो सकती है। विश्व में सिर्फ भारत ने इंडियन कूलिंग एक्शन प्लान नामक एक राष्ट्रीय नीति का प्रारूप तैयार किया है। इससे एसी से निकलने वाली गर्म हवा के प्रकोप से वातावरण को सुरक्षित किया जा सकता है। अहमदाबाद समूचे दक्षिण एशियाई देशों में पहला ऐसा शहर बना जिसने इसके प्रभाव से निपटने के लिए हीट एक्शन प्लान बनाया। इस योजना को भारत के अन्य 17 शहरों और 11 राज्यों में धरातल पर लाने की कोशिश की जा रही है। फिलहाल भारत में 7 प्रतिशत प्रतिशत लोग अपने घरों में एसी इस्तेमाल करते हैं। विकसित देशों अमेरिका और जापान में 90 प्रतिशत लोग एसी का उपयोग करते हैं। भारत सरकार ने कुछ निजी कंपनियों के साथ करार कर राजधानी दिल्ली के 25 लाख घरों में इस उपकरण को 40 प्रतिशत तक अधिक प्रभावी बनाने का लक्ष्य रखा है। आंकड़ों के अनुसार विश्व में करीब 1.6 अरब लोग अपने घरों एवं कार्यस्थलों पर एसी का इस्तेमाल करते हैं। वर्ष 2050 तक इसके 5.6 अरब होने की संभावना है। सरकार के साझा प्रयास से आमजन अपने सुझाव और अपने आविष्कार भेज कर ग्लोबल कूलिंग प्राइज में हिस्सा लेकर इस समस्या का हल निकालने में मदद कर सकते हैं। विकसित देशों को भारत की इस नीति से सीख लेनी चाहिए।

उद्देश्य कुमार, मणिपाल

भारत ने इंडियन कूलिंग एक्शन प्लान नामक एक राष्ट्रीय नीति का प्रारूप तैयार किया है

देश में नए तेल क्षेत्र खोजे सरकार

कच्चे तेल की कीमतें बढ़ रही हैं। इससे हमें तेल खरीदने में ज्यादा खर्च करना पड़ेगा। इसका सीधा असर किराये पर जाएगा तो वस्तु की कीमतें भी बढ़ेंगी। इससे महंगाई भी बढ़ेगी जिससे लोगों की आर्थिक व वित्तीय स्थिति बदतर होगी। ऐसे में सरकार को चाहिए कि वे बाड़मेर क्षेत्र में नए-नए तेल के कुएं से तेल निकाले। इसके लिए ठोस सरकारी प्रयासों की जरूरत है। इससे हमें विदेशों से तेल नहीं खरीदना पड़ेगा। सरकार को तेल खोज कार्यक्रम को प्राथमिकता देनी होगी तभी हमारी आवश्यकताएं भी पूरी होंगी। इसके अलावा चार पहिया तथा दो पहिया वाहनों पर भी नियंत्रण करना होगा। देश में रोजाना हजारों वाहन सड़कों पर उतर रहे हैं जिससे ईंधन की खपत बढ़ेगी।

पाठक अपनी राय हमें इस पते पर भेज सकते हैं : संपादक, बिजनेस स्टैंडर्ड लिमिटेड, 4, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली - 110002. आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं : lettershindi@bsmail.in उस जगह का उल्लेख अवश्य करें, जहां से आप ईमेल कर रहे हैं।